The Economic Times (Hindi)
21-6-13

शुगर PDS के नए सिस्टम के लिए कम राज्य तैयार

[श्रेया जय *नई दिल्ली*]

केंद्र के शुगर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के खत्म होने में बमुश्किल 10 दिन बचे हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर अभी तक किसी भी राज्य ने राशन दुकानों के लिए लेवी शुगर नहीं खरीदी है। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है, जिसने चीनी खरीदने के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास पहले से कुछ लेवी शुगर पड़ी है, जो कुछ समय तक चलेगी।

नई प्रोक्योरमेंट स्कीम के लिए प्रपोजल राज्य सरकारों के पास पेंडिंग है। यूपी, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी को-ऑपरेटिव मिलों से चीनी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। दूसरे राज्यों को राशन दुकानों के लिए चीनी खरीदने का प्रोसेस शुरू करने की योजना बनानी है।

जम्मू एंड कश्मीर और नार्थ-ईस्ट राज्य लॉजिस्टिक दिक्कतों की दुहाई दे रहे हैं। वे नया सिस्टम अपनाने के लिए 3 महीने से लेकर 1 साल की मोहलत मांग रहे हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के एक सीनियर अफसर के मुताबिक, 'हम राज्यों को कम से कम तीन महीने का एडवांस अमाउंट दे रहे हैं, ताकि वे शुगर पीडीएस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें। हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) और प्राइवेट मिलर्स से भी बात कर रहे हैं कि वे नॉर्थ-ईस्ट और जेएंडके में वेयरहाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं।'

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इसके लिए ज्यादा वक्त की मांग करना या इसमें बदलाव करना बेमतलब होगा। नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों ने अपने यहां स्टोरेज सुविधाओं की कमी की चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे ऑपरेशन की एक्चुअल कॉस्ट केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी से ज्यादा होगी।

मिजोरम सरकार ने फूड मिनिस्ट्री को लिखे लेटर में कहा है, 'पीडीएस के लिए शुगर की नई स्कीम को तब तक सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, जब तक केंद्र सरकार कम से कम 25 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी नहीं देती।' पीडीएस मामलों से जुड़े हुए एक अधिकारी ने कहा, 'यह कैबिनेट का फैसला है और सब्सिडी अमाउंट में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, हम कास्टिंग पैटर्न पर दोबारा नजर डाल रहे हैं और एडवांस पेमेंट तेज कर सकते हैं।' जून से केंद्र सरकार ने देश भर में राशन दुकानों के लिए मिलों से चीनी खरीदना बंद कर दिया है। राज्यों को ओपन मार्केट से टेंडर के जरिए चीनी खरीदनी होगी।

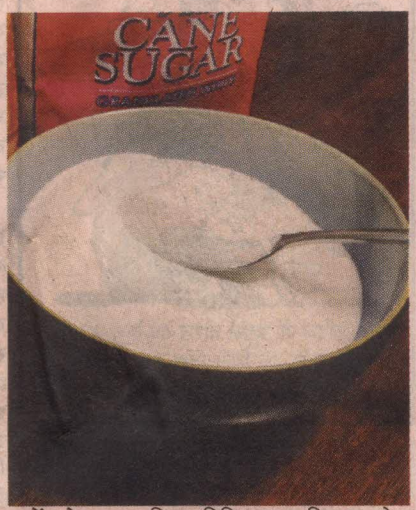

- **केंद्र के** शुगर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के खत्म होने में महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर अभी तक किसी राज्य ने राशन दुकानों के लिए लेवी शुगर नहीं खरीदी
- **जम्मू एंड** कश्मीर और नार्थ-ईस्ट के राज्य लॉजिस्टिक दिक्कतों की दुहाई देकर नया सिस्टम अपनाने के लिए 3 महीने से लेकर 1 साल की मोहलत मांग रहे हैं